मंडल की 50 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 70 करोड़ का अनुदान स्वीकृत

राज्य स्तरीय एंपॉवर्ड कमेटी की बैठक में प्रस्तावित अनुदान पर लगी मुहर

अमर उजाला ब्यूरो

बरेली। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के हब के तौर पर पहचान बना रहे बरेली मंडल के उद्यमियों को उद्योग संचालन के लिए प्रस्तावित अनुदान पर शासन की मुहर लग गई है। राज्य स्तरीय एंपॉवर्ड कमेटी ने 50 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 70 करोड़ के अनुदान के लिए मंजूरी दे दी है।

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र बरेली के कार्यालय प्रभारी अंशिल सिन्हा के मुताबिक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत इकाइयों को अनुदान की मंजूरी मिली है। इसमें दुग्ध प्रसंस्करण, रेडी-टू-ईट, मसाला प्रोसेसिंग, फ्रोजन फूड, नमकीन, ब्रेड, मल्टीग्रेन आटा, स्नैक्स, जैगरी उत्पाद, ऑयल मिल, सोलर पॉवर आदि के प्रस्ताव शामिल रहे। जिन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एंपॉवर्ड कमेटी की बैठक में स्वीकृति मिली। प्रस्तावों पर उद्यमियों को 35 से 50 फीसदी और सौर ऊर्जा लगाने पर 90 फीसदी का अनुदान स्वीकृत किया है।

कार्यालय प्रभारी के मुताबिक, अनुदान मिलने से पहले ही मंडल की कई इकाइयों में उत्पाद बनने भी लगे हैं। जिन इकाइयों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ, अनुदान मिलने से इस अड़चन का भी निदान हो जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण इकाई में तैयार किए जा रहे उत्पाद। *संवाद*

अनुदान हासिल करने वाले मंडल के प्रमुख उद्योग

जिला	यूनिट	प्रसंस्कृत उत्पाद	अनुदान
पीलीभीत	डीएस फ्रोजन फूड	फ्रोजन	8.56 करोड़
पीलीभीत	बांसुरी इंडस्ट्रीज	फ्रोजन	08 करोड़
पीलीभीत	नैवेद्य एग्री फूड्स	मुरमुरे, पोहा, राइस	05 करोड़
शाहजहांपुर	एसपीकेएन इंडस्ट्री	लिक्विड ग्लूकोज	9.36 करोड़
शाहजहांपुर	केदारनाथ एग्रो	मल्टीग्रेन प्रोडक्ट	2.47 करोड़
शाहजहांपुर	एमके जैगरी इंडस्ट्री	जैगरी पाउडर	1.32 करोड़
बरेली	एरीना सॉल्वेक्स	ऑयल	05 करोड़
बरेली	कनकधाम फूड्स	मल्टीग्रेन	4.36 करोड़
बरेली	साध्या प्रोडक्ट्स	नमकीन, स्नैक्स	4.63 करोड़
बरेली	स्कैप्स फूड्स	मल्टीग्रेन	2.5 करोड़

(नोट: अनुदान के आंकड़े राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के अनुसार)

उद्यमी बोले- कच्चा माल उपलब्ध, बेहतर है उद्योग नीति

लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष उन्मुक्त संभव शील के मुताबिक, बरेली मंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता है। खाद्य तेल, रस्क, ब्रेड, स्नैक्स, बिस्किट, कचरी, चिप्स, सोया, आचार, पापड़, फ्रोजन फूड्स आदि की हजार से ज्यादा इकाइयां संचालित हैं। जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा के मुताबिक, लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्योग नीतियों की जरूरत है, जिसका लाभ उद्यमियों को मिल रहा है।